

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन  
गोमती नगर, लखनऊ

सेवा में,

Dr. Zakari Adam  
चीफ - फील्ड ऑफिस, यूनीसेफ  
उ0 प्र0, बी-3/258, विशाल खंड  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: 5127 / 3894 / वादा संखी/2022-23 लखनऊ:

दिनांक: ११ दिसंबर, 2022

बिषय: ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं यूनीसेफ के मध्य एम0ओ0यू० पायलट परियोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि ग्राम्य विकास विभाग और यूनीसेफ के मध्य एम0ओ0यू० दिनांक 17.02.2022 के सदर्भ में प्रदेश के 37 जनपदों के 7,228 ग्राम पंचायतों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों तक शासन के अलग-अलग विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ डी0बी0टी0 के माध्यम से पहुंचाने का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है। इस के दृष्टिगत, यूनीसेफ द्वारा एक विशेष पायलट परियोजना के संचालन में सहायता दी जा रही है। पायलट परियोजना के तहत चुने गये ग्राम पंचायतों में एक-एक समूह सखी का चयन होना प्रस्तावित था। जिसके क्रम में अबतक 7,228 ग्राम पंचायतों में से 6,108 ग्राम पंचायतों में समूह सखी अध्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5,448 समूह सखी चयनित हुए हैं।

पायलट प्रोजेक्ट के टाइमलाइन अंतर्गत ज्ञानी स्तर पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सूचन करने की दृष्टि से जनपद श्रावस्ती के 5 ग्राम पंचायत में विशेष कैंपेन प्रारंभ किया गया है ताकि टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर की संपूर्णता तथा लाभार्थी तक डीबीटी प्राप्ति की उपलब्धि की स्थिति प्राप्त किया जा सके। आप अवगत हैं, श्रावस्ती के 5 ग्राम पंचायत में स्थित समूहों के साथ MGNREGA योजना के लाभ आहरण के विशेष कार्य योजना पर अपेक्षित गति से कार्य प्रगति में हैं। आगामी कुछ दिनों में वादा समूह सखी तथा समूह सदस्यों के लिए डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण का प्रारूप भी संचालित होना प्रस्तावित है।

उक्त के क्रम में, यूनीसेफ प्रोग्राम मैनेजर, डॉ अमित मेहरोत्रा के साथ दिनांक नवंबर 29, 2022 को हुई वार्ता के अनुसार अभी भी एम0ओ0यू० के अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं हुई है। ये भी संज्ञान लिया गया है कि एम0ओ0यू० की समय सीमा 31 दिसंबर 2022 तक ही है। सभी अन्य जनपदों में कार्य के प्रगति के दृष्टिगत परियोजना के प्रक्रिया को जारी रखना आवश्यक है। ये भी विचारणीय है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीने में डीबीटी लाभ का भुगतान तथा आहरण की विशेष संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में, पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के प्रक्रिया को ना सिफ़े बढ़ाया जाना सही प्रतीत होता है, बल्कि डिजिटल सेट अप बन जाने से कार्य में जो गति प्राप्त हुई है, उसे भी जारी रखा जाना उचित होगा।

कृपया उपरोक्त के दृष्टिगत एम0ओ0यू० को 31 मई 2023 तक विस्तार किये जाने विचार करे जिससे कि आपके सहयोग से मिशन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यूनीसेफ द्वारा संबद्ध एंजेंसी को भी इस आशय से नो-कॉस्ट एक्सटेंशन देते हुए सूचित किया जाये ताकि टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म का निरंतरता एवं मिशन द्वारा डिजिटल सेवाओं का उपयोग जारी रखा जा सके।

भवदीय  
(सौ. इंदुमती)  
मिशन निदेशक,  
उ0 प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

पत्रांक संख्या - / वादा संखी/2022-23, लखनऊ: तद दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थी और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- डॉ अमित मेहरोत्रा, प्रोग्राम मैनेजर, यूनीसेफ
- सुश्री पियूष एंटनी, सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ

मिशन निदेशक,  
उ0 प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन  
गोमती नगर, लखनऊ

सेवा में,

Dr. Zakari Adam  
चीफ - फ़िल्ड ऑफिस, यूनीसेफ  
उ0 प्र0, बी-3/258, विशाल खंड  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक:

/

/वादा सखी/2022-23 लखनऊ:

दिनांक: ०१ दिसंबर, 2022

बिषय: ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं यूनीसेफ के मध्य एम0ओ0यू० पायलट परियोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है की ग्राम्य विकास विभाग और यूनीसेफ के मध्य एम0ओ0यू० दिनांक 17.02.2022 के सदर्भ में प्रदेश के 37 जनपदों के 7,228 ग्राम पंचायतों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों तक शासन के अलग-अलग विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ डी0बी0टी० के माध्यम से पहुंचाने का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है। इस के दृष्टिगत, यूनीसेफ द्वारा एक विशेष पायलट परियोजना के संचालन में सहायता दी जा रही है। पायलट परियोजना के तहत चुने गये ग्राम पंचायतों में एक-एक समूह सखी का चयन होना प्रस्तावित था। जिसके क्रम में अबतक 7,228 ग्राम पंचायतों में से 6,108 ग्राम पंचायतों में समूह सखी अध्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5,448 समूह सखी चयनित हुए हैं।

पायलट प्रोजेक्ट के टाइमलाइन अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सूचन करने की दृष्टि से जनपद श्रावस्ती के 5 ग्राम पंचायत में विशेष कैपेन प्रारंभ किया गया है ताकि टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर की संपूर्णता तथा लाभार्थी तक डीबीटी प्राप्ति की उपलब्धि की स्थिति प्राप्त किया जा सके। आप अवगत हैं, श्रावस्ती के 5 ग्राम पंचायत में स्थित समूहों के साथ MGNREGA योजना के लाभ आहरण के विशेष कार्य योजना पर अपेक्षित गति से कार्य प्रगति में हैं। आगामी कुछ दिनों में वादा समूह सखी तथा समूह सदस्यों के लिए डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण का प्रारूप भी संचालित होना प्रस्तावित है।

उक्त के क्रम में, यूनीसेफ प्रोग्राम मैनेजर, डॉ अमित मेहरोत्रा के साथ दिनांक नवंबर 29, 2022 को हुई वार्ता के अनुसार अभी भी एम0ओ0यू० के अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं हुई है। ये भी संज्ञान लिया गया है कि एम0ओ0यू० की समय सीमा 31 दिसंबर 2022 तक ही है। सभी अन्य जनपदों में कार्य के प्रगति के दृष्टिगत परियोजना के प्रक्रिया को जारी रखना आवश्यक है। ये भी विचारणीय है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीने में डीबीटी लाभ का भुगतान तथा आहरण की विशेष संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में, पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के प्रक्रिया को ना सिर्फ बढ़ाया जाना सही प्रतीत होता है, बल्कि डिजिटल सेट अप बन जाने से कार्य में जो गति प्राप्त हुई है, उसे भी जारी रखा जाना उचित होगा।

कृपया उपरोक्त के दृष्टिगत एम0ओ0यू० को 31 मई 2023 तक विस्तार किये जाने विचार करे जिससे कि आपके सहयोग से मिशन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यूनीसेफ द्वारा संबद्ध एजेंसी को भी इस आशय से नो-कॉस्ट एक्सटेंशन देते हुए सूचित किया जाये ताकि टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म का निरंतरता एवं मिशन द्वारा डिजिटल सेवाओं का उपयोग जारी रखा जा सके।

भवदीय

(सी0 इंदुमती)

मिशन निदेशक,

उ0 प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

पत्रांक संख्या - ५१२७ / ३८९५ / वादा सखी/2022-23, लखनऊ: तद दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थी और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. डॉ अमित मेहरोत्रा, प्रोग्राम मैनेजर, यूनीसेफ
2. सुश्री पियूष एंटनी, सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ

५१२७

मिशन निदेशक,

उ0 प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन  
गोमती नगर, लखनऊ

सेवा में,

Dr. Zakari Adam  
चीफ - फ़िल्ड ऑफिस, यूनीसेफ  
उ0 प्र0, बी-3/258, विशाल खंड  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: ५१२७ /३८९४ /वादा सखी/2022-23 लखनऊ:

दिनांक: ०१ दिसम्बर, 2022

बिषय: ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं यूनीसेफ के मध्य एम०ओ०य० पायलट परियोजना के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है की ग्राम्य विकास विभाग और यूनीसेफ के मध्य एम०ओ०य० दिनांक 17.02.2022 के सदर्व में प्रदेश के 37 जनपदों के 7,228 ग्राम पंचायतों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों तक शासन के अलग-अलग विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ डीबी०टी० के माध्यम से पहुंचाने का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है। इस के दृष्टिगत, यूनीसेफ द्वारा एक विशेष पायलट परियोजना के संचालन में सहायता दी जा रही है। पायलट परियोजना के तहत चुने गये ग्राम पंचायतों में एक-एक समूह सखी का चयन होना प्रस्तावित था। जिसके क्रम में अबतक 7,228 ग्राम पंचायतों में से 6,108 ग्राम पंचायतों में समूह सखी अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5,448 समूह सखी चयनित हुए हैं।

पायलट प्रोजेक्ट के टाइमलाइन अंतर्गत ज्ञानी स्तर पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सूझन करने की दृष्टि से जनपद श्रावस्ती के 5 ग्राम पंचायत में विशेष कैंपेन प्रारंभ किया गया है ताकि टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर की संपूर्णता तथा लाभार्थी तक डीबी०टी० प्राप्ति की उपलब्धि हो सके। आप अवगत हैं, श्रावस्ती के 5 ग्राम पंचायत में स्थित समूहों के साथ MGNREGA योजना के लाभ आहरण के विशेष कार्य योजना पर अपेक्षित गति से कार्य प्रगति में हैं। आगामी कुछ दिनों में वादा समूह सखी तथा समूह सदस्यों के लिए डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण का प्रारूप भी संचालित होना प्रस्तावित है।

उक्त के क्रम में, यूनीसेफ प्रोग्राम मैनेजर, डॉ अमित मेहरोत्रा के साथ दिनांक नवंबर 29, 2022 को हुई वार्ता के अनुसार अभी भी एम०ओ०य० के अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं हुई है। ये भी संज्ञान लिया गया है कि एम०ओ०य० की समय सीमा 31 दिसम्बर 2022 तक ही है। सभी अन्य जनपदों में कार्य के प्रगति के दृष्टिगत परियोजना के प्रक्रिया को जारी रखना आवश्यक है। ये भी विचारणीय है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीने में डीबी०टी० लाभ का भुगतान तथा आहरण की विशेष संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में, पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के प्रक्रिया को ना सिर्फ बढ़ाया जाना सही प्रतीत होता है, बल्कि डिजिटल सेट अप बन जाने से कार्य में जो गति प्राप्त हुई है, उसे भी जारी रखा जाना उचित होगा।

कृपया उपरोक्त के दृष्टिगत एम०ओ०य० को 31 मई 2023 तक विस्तार किये जाने विचार करे जिससे कि आपके सहयोग से मिशन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यूनीसेफ द्वारा संबद्ध एजेंसी को भी इस आशय से नो-कॉस्ट एक्सटेंशन देते हुए सूचित किया जाये ताकि टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म का निरंतरता एवं मिशन द्वारा डिजिटल सेवाओं का उपयोग जारी रखा जा सके।

भवदीय

०१/११२/२०२२  
(सा० इंदुपर्ती)  
मिशन निदेशक,  
उ० प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

पत्रांक संख्या - ५१२७ /३८९४ /वादा सखी/2022-23, लखनऊ: तद दिनांक-  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० अमित मेहरोत्रा, प्रोग्राम मैनेजर, यूनीसेफ
2. सुश्री पियूष एंटनी, सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ

०१/११२/२०२२  
मिशन निदेशक,  
उ० प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन